



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 17, 1980/माघ 28, 1901

No. 35] NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 17, 1980/MAGHA 28, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

प्रधिकार सूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1980

सां. का० नि० 48 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित  
उद्घोषणा संबंधान के मूल्यांकन की जा रही है:

यह: भैरव, भारत के राष्ट्रपति, नीलम संजीव रेहड़ी का समाधान हो गया है  
कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें कि मध्य प्रदेश राज्य का शासन  
भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संविधान” कहा गया है)  
के उपचान्दों के अनुसार नहीं बलाया जा सकता है;

प्रतः इस मैं संविधान के मनुष्ठेद 356 द्वारा प्रदत्त अक्षियों का तथा उस  
निमित्त मूर्म समय बनाने वाली मध्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
प्रत्येक उद्घोषणा करता हूँ कि मैं—

- (क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्य-  
पाल में निहित या एतद्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, भारत  
के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूँ;
- (ख) आवित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियाँ  
संसद के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होती हैं; और
- (ग) निम्नलिखित प्रानुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूँ  
जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों की प्रभावी करने के लिये  
मुझे प्रावश्यक या बाधकीय भर्ती होते हैं; अर्थात्—
- (i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त छंड (क) के आधार पर  
अपने हाथ में लिये गये कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग  
करने में, मेरे लिये भारत के राष्ट्रपति के रूप में उम सीमा  
तक जिस तक मैं ठीक समूँ उक्त राज्य के राज्यपाल के  
माध्यम से कार्य करता विधिवूर्ण होगा;

(ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों  
के प्रवर्तन को एतद्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात्—

मनुष्ठेद 3 के परत्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति  
द्वारा राज्य के विधान मंडल को निश्चय करने से है;

मनुष्ठेद 151 के छंड (2) का उतना भाग जितने  
का संबंध भारत के नियंत्रक महानेता परीक्षक द्वारा  
राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान  
मंडल के समझ रखे जाने से है;

मनुष्ठेद 163 और 164;

मनुष्ठेद 166 के छंड (3) का उतना भाग जितने का  
संबंध राज्य सरकार के कार्यों का अंतिम के बीच  
प्रावंटन से है; मनुष्ठेद 167 और मनुष्ठेद 169 के  
छंड (1) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की  
विधान सभा द्वारा संकल्प के परित किये जाने से है;

मनुष्ठेद 174 का छंड (1) और छंड (2) का उपर्युक्त  
(क); मनुष्ठेद 175 से 178 तक (जिसमें ये  
दोनों सम्मिलित हैं); मनुष्ठेद 179 का छंड (ख)  
और (ग) और उस मनुष्ठेद का प्रथम परत्तुक और  
मनुष्ठेद 180 और 181;

मनुष्ठेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा  
के उपाध्यक्ष के संबलमो और भर्ती से है, मनुष्ठेद  
188, 189, 193, 194, 195 तक 196; मनुष्ठेद 198;  
मनुष्ठेद 199 का छंड (3) और छंड (4);

मनुष्ठेद 202 के अंडे (3) का उतना भाग जिनसे का संबंध विधान सभा के उपायक के संबलमों और भरतीं से है, मनुष्ठेद 208 से 211 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं; मनुष्ठेद 213 के अंडे (1) का परन्तु और अंडे (3) का परन्तु; और

मनुष्ठेद 323 के अंडे (2) का उतना भाग जिनसे का संबंध राष्ट्रपति रिपोर्ट को राष्ट्र विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है;

- (iii) उक्त राष्ट्र की विधान सभा एवं भारत विधान सभा की जाती है;
- (iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निवेश का ग्रथं उस राष्ट्र के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के प्रति निवेश लगाया आएगा और उसमें राष्ट्र के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति किसी निवेश का, जहाँ तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अप्रति जब तक कि संघर्ष में लगाया गयेकितन ही, संसद के प्रति निवेश लगाया जाएगा, और विशिष्टतमा मनुष्ठेद 213 में राज्यपाल और राष्ट्र के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति निवेश का ग्रथं क्रमशः राष्ट्रपति और मंसद या उसके सदनों के प्रति निवेश लगाया जायेगा;

परन्तु इसमें कोई बात मनुष्ठेद 153, मनुष्ठेद 155 से लेकर मनुष्ठेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) मनुष्ठेद 299 और मनुष्ठेद 361 तथा द्वितीय मनुष्ठेद के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं दालेंगे और न राष्ट्रपति को इस बाणी के उपबन्ध (1) के ग्रथीन उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक समझ, उक्त राष्ट्र के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने में निवारित करेंगी;

- (v) संविधान में राष्ट्र के विधान मण्डल के या एनवडाग बनाए गए प्रधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निवेश का ऐसे ग्रथं लगाया जाएगा मानों उसके अन्तर्गत इस उद्दोषण के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के मनुष्ठेद 357 के अंडे (1) के उपबन्ध (क) में निविष्ट ग्रन्थ प्रधिकारी द्वारा राष्ट्र के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा बनाए गए प्रधिनियमों या विधियों के प्रति निवेश है. और मध्य प्रदेश साधारण बाणी प्रधिनियम, 1957 (मध्य प्रदेश 1958 का प्रधिनियम 3), जिस तर्फ में मध्य प्रदेश राष्ट्र में सागू है और साधारण बाणी प्रधिनियम, 1897 (1897 के 10वें) का उतना भाग जितना राष्ट्र विधियों पर नागू है, ऐसे किसी प्रधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानों यह उस राष्ट्र के विधान मण्डल का प्रधिनियम हो।

महे विल्सी;

17 फरवरी, 1980

नोलम संजीव रेड्डी,

राष्ट्रपति

[संभा V/11013/4/80-सी एस आर]

महे विल्सी;

17 फरवरी, 1980

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February 1980

G.S.R. 48(E).—The following Proclamation by the President is published for general information :

Whereas, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Madhya Pradesh cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament ; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—
  - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State ;
  - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely :—
    - so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State ;
    - so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India ;
    - articles 163 and 164 ;
    - so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State ; article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State ;
    - clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174 ; articles 175 to 178 (both inclusive) ; clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181 ;
    - so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly ; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196 ; article 198 and clause (3) and (4) of article 199 ;
    - so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly ; articles 208 to 211 (both inclusive) ; the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213 ; and
    - so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State ;
  - (iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved ;
  - (iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the

Legislature of the State or the Houses thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively :

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 291 and articles 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the Madhya Pradesh General Clauses Act, 1957 (Madhya Pradesh Act 3 of 1958) as in force in the State of Madhya Pradesh, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi:

The 17th February, 1980.

NEELAM SANJIVA REDDY,

President.

[No. V/11013/4/80-CSR]

New Delhi:

The 17th February, 1980.

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Secy.

प्रादेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1980

सांकेति 49(अ).—गांधीजी द्वारा जारी किया गया निम्न-लिखित प्रादेश संविधान के मूल्यनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज करवाई, 1980 के 17वें दिन जारी की गई उद्घोषणा के अन्त (ग)

के उपचारण (1) का अनुग्रहण करते हुए मैं एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के प्रधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उग राज्य के राज्यपाल में निहित या प्रयोक्तव्य सभी अस्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के अन्त (क) के आधार पर अपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के प्रधीकरण, निर्वेशन और नियन्त्रण के अध्याधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

नई दिल्ली;

17 फरवरी, 1980

नीलम संजीव रेडी,

राष्ट्रपति

[सं. V/11013/4/80-सी. एम आर]

नई दिल्ली;

17 फरवरी, 1980

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 17th February, 1980

**G.S.R. 49(E).**—The following Order by the President is published for general information :

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 17th day of February, 1980, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Madhya Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi; The 17th February, 1980.

NEELAM SANJIVA REDDY,  
President.

[No. V/11013/4/80-CSR]

New Delhi; T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Secy.  
The 17th February, 1980.

